यूपी को कृषि, महिला व इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ी हिस्सेदारी

- यूपी को नहीं मिली कोई बड़ी योजना, हिस्सेदारी बढ़ी
- 25 हजार करोड़ ज्यादा मिलने से तेज होगा विकास

उत्तर प्रदेश

■ आनंद सिन्हा

लखनऊ। केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश के लिए किसी बड़ी विशेष योजना की घोषणा नहीं हुई है। इसे भले ही सियासी दल यूपी में लोकसभा की घटी हुई सीटों का प्रतिकूल असर करार दें लेकिन यूपी को केंद्रीय बजट से पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 25600 करोड़ रुपये की धनराशि ज्यादा मिलेगी। यह धनराशि यूपी को केंद्रीय करों व शुल्क से मिलने वाली कुल राशि 2 लाख 23 हजार 737.23 करोड़ रुपये में बढ़ोतरी से हासिल होगी। वहीं कृषि, महिलाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर, मुद्रा लोन, एमएसएमई के हिस्से में भी यूपी को आबादी के मुताबिक बड़ी धनराशि मिलना तय है।

केंद्रीय बजट में कृषि के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये की जो व्यवस्था की गई है, उसमें से यूपी को बड़ी धनराशि मिलेगी। इसमें से यूपी के करीब 2.62 करोड़ से ज्यादा पंजीकृत किसान लाभांवित होंगे। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिए जाने का भी लाभ यूपी को मिलेगा। आधी आबादी के लिए विभिन्न योजनाओं में निर्धारित किए गए 3 लाख करोड़ रुपये में से भी बड़ा हिस्सा यूपी को मिलना तय है। ग्रामीण इलाकों में कार्य कर रहे 75 लाख से अधिक महिला सहायता समूह की महिलाओं को इसका लाभ मिलना तय है। बजट में स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट का बड़ा हिस्सा भी प्रदेश की महिलाओं को मिलेगा।

यूपी के हिस्से में बढ़ी राशि

- केंद्र प्रायोजित योजनाओं में पहले 90 हजार करोड़ मिलने थे अब मिलेंगे 96 हजार करोड़
- केंद्रीय योजनाओं में करीब 7000 करोड़ मिलने थे, अब मिलेंगे 11500 करोड़
- विकसित भारत योजना में यूपी को मिलने थे 14000 करोड़, यह राशि यथावत
- विशेष योजनाओं में मिलने थे 17939 करोड़, यह राशि भी यथावत

यूपी को इस वित्तीय वर्ष में मिल सकते हैं 45 लाख पीएम आवास

इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में सभी राज्यों के लिए करीब 30171 करोड़ रुपये अधिक की व्यवस्था की है। यह पिछले वित्तीय वर्ष से 8000 करोड़ अधिक है। ऐसे में यूपी को इसमें भी बड़ी धनराशि मिलने का अनुमान है।

इसी तरह प्रधानमंत्री आवास में करीब 3 करोड़ आवास बनाने की घोषणा हुई है। ग्रामीण विकास पर फोकस रखते हुए केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पिछले वर्ष की तुलना में 22500 करोड़ रुपये की अधिक व्यवस्था की गई है।

पीएम आवास की दोनों योजनाओं में भी करीब 45 लाख मकान यूपी के हिस्से में आने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्टर के क्षेत्र में 11.10 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान रखा गया है। इसके चलते विकास योजनाओं में भी यूपी को बड़ी धनराशि मिलना तय है।